lives of lakhs of people. The problem is regarding working of the Jhilmil District of the Delhi Electric Supply Undertaking.

Matters Under Rule 377

The lighting arrangements even on the main roads of national importance like the G.T. Road from the old Yamuna Bridge upto the U.P. border are very inadequate.

There are no lights on the road beyond Preet Vihar to Anand Vihar and U.P. border. This is in spite of the fact that the I and B. Minister himself has assured the residents of the area that this would be done shortly. However, no action has been taken so far by DESU.

Domestic connections to the intending small house builders of the approved colonies are very much delayed.

There is too much delay in installing connections even when all the necessary facilities are provided by the consumers

The maintenance of the street lights in colonies like Yojana Vihar is so poor that this has caused a lot of fear in the minds of the residents about their proper security. This is so in spite of many written complaints.

The engineers and the officers of the Jhilmil District are hardly available in their rooms most of the time and the reply given is that they have gone for site inspection.

I, therefore, suggest that a high level inquiry be conducted into the working of the Jhilmil district. Unless, this is done immediately, I am afraid that the situation would worsen day by day.

(iv) Financial help to Rajasthan Government for repairs of roads damaged due to military exercises

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (वाड़मेर): उपाध्यक्ष महो-दय, राजस्थान प्रान्त के सीमावर्ती, वाड़मेर, जैस-लमेर, बीकानेर, जोधपुर एवं गंगानगर जिलो मे थल सेना का सैनिक अभ्यास कार्य करीब 15 वर्षो से सर्दी के दिनों में प्रतिवर्ष चल रहा है। थल सेना अभ्यास के समय बड़े-बड़े वाहनो, टैकरों आदि का प्रयोग करती है। उक्त बाहनों के प्रयोग के कारण राज्य की सैंकड़ों सड़कें तहस-नहस एवं क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण राज्य को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है।

राज्य की जनता का आवागमन मे बाधा के कारण बड़े कष्ट का सामना करना पड़ रहा है।

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की नही है, जो प्रतिवर्ष उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य हाथ में ले।

अतः केन्द्र सरकार के रक्षा विभाग से निवेदन है कि वे अपने प्रतिनिधि को तुरन्त मौके पर भेजें और राज्य सरकार के प्रतिनिधि को साथ में लेकर सम्पूर्ण नुकसान का पता लगाकर राज्य सरकार को मुआवजे के रूप में तुरन्त से तुरन्त राशि प्रदान कराएं, ताकि गर्मी की वर्षा से पहले-पहले उक्त सड़कों की मरम्मत एवं सुधार का कार्य संपूर्ण किया जा मके।

14.37 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

(v) Need to restore the earlier admission policy in J.N.U.

श्री बी॰डी॰ सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने 1973 में प्रवेश की एक ऐसी नीति को स्वीकृति किया था एवं सत्र 1974-75 से कियान्वित किया था, जिससे निबंल वर्ग के तथा सामाजिक आधिक दृष्टि से पिछड़े तथा पिछड़े क्षेत्रों के परिवारों के छात्रों को विशेष सुविधा प्रदान करके उन्हे विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर सुलभ कर दिया जाता था। परन्तु अभी हाल में विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने निर्णय लेकर उस प्रवेश नीति को समाप्त कर दिया। इसका परिणाम यह होगा कि उन छात्रों को, जो सामाजिक, आर्थिक अथवा क्षेत्रीय दृष्टि से पिछड़े है, प्रवेश के समय अंकों में वह छूट नहीं प्रदान की जाएगी, जो पूर्व प्रवेश नीति के अन्तर्गत प्रदान की जाती थी।